

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 30 अगस्त, 2022

निर्णय लिया गया: 10 जनवरी, 2023

सि.वा. (मू.प.) 420/1982

ध्रुव गोयल और अन्य

..... वादीगण

द्वारा: श्री त्रिदीप पेस, वरिष्ठ अधिवक्ता  
सह श्री शिवम शर्मा एवं श्री सुदक्षिणा  
प्रसाद, अधिवक्तागण।

विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आनंद प्रकाश गोयल और अन्य ....प्रतिवादी

द्वारा: श्री कुणाल टंडन, श्री अजय शेखर,  
सुश्री नीति जैन, श्री अमनदीप सिंह  
एवं सुश्री आंचल खन्ना, प्रति-2 के  
अधिवक्तागण। श्री आशीह जैन, श्री  
आदर्श कुमार गुप्ता और श्री केशव  
मान, प्रति-14 से 16 के  
अधिवक्तागण। सुश्री श्रिया अग्रवाल,  
अं.आ. 14901/2021 की आवेदक-  
सुनीता गुप्ता और डी.(सी) और  
डी.(जी) के लिए अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

## निर्णय

न्या. नीना बंसल कृष्णा

अं.आ. 8468/2009

1. 1982 में विधवा बहू और उसके बच्चों द्वारा ससुर और बहनोईयों के विरुद्ध बँटवारे के लिए एक पारिवारिक मुकदमा शुरू किया गया था और 40 साल बीत जाने के बावजूद, यह मुकदमा समाप्त होता नहीं दिख रहा है। यह न केवल हमारी न्यायिक प्रणाली की आलोचना है, बल्कि पक्षकारगण के लिए एक स्पष्ट आह्वान भी है कि वे भावी पीढ़ियों के लिए मुकदमेबाज़ी की विरासत छोड़ने के बजाय अपने पारिवारिक विवादों को निपटाने का प्रयास करें।

2. प्रतिवादी सं. 2, श्री वीरेंद्र कुमार गोयल की ओर से आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली में संपत्ति के कब्जे हेतु शुल्क के भुगतान के लिए वादीगण को निर्देश देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (*इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित*) के तहत एक आवेदन दायर किया गया है।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने अनुसूची क में उल्लिखित पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन के लिए; अनुसूची ख में उल्लिखित संपत्तियों के लेखे का विवरण देने और धन की वसूली के लिए एक वाद दायर किया है। अनुसूची-क में उल्लिखित संपत्तियों में से एक संपत्ति संख्या 29-ए/1, आसफ़ अली रोड, नई दिल्ली का बेसमेंट और तीसरी मंज़िल है। यह मूल रूप से

साझेदारी फर्म आर.एस. माधो राम एंड संस की थी। 01.05.1964 को संपत्ति का बँटवारा निम्नानुसार किया गया:

**(i) बेसमेंट और तीसरी मंज़िल:**

श्री आनंद प्रकाश गोयल (प्रतिवादी सं. 1) - 51.50%

श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल (प्रतिवादी सं. 2) - 4.25%

श्री सुरेश कुमार गोयल (वादीगण का पूर्वाधिकारी) -  
24.25%

4. श्री आनंद प्रकाश गोयल, प्रतिवादी सं. 1 (वादी सं. 3 के ससुर) ने अपनी अंतिम विल दिनांक 12.12.1987 को निष्पादित की, जिसमें उसने संपत्ति में अपना 51.50% का हिस्सा श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल, प्रतिवादी सं. 2 और श्री रविंदर कुमार गोयल, प्रतिवादी सं. 3 को क्रमशः 26.50% और 25% के अनुपात में दे दिया। वसीयत को स्वर्गीय श्री आनंद प्रकाश गोयल के सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

5. बेसमेंट एएनजेड ग्रिंडलेज़ बैंक की किरायेदारी के तहत था, जिसने इसे खाली कर दिया और वादी और प्रतिवादी सं. 2 को चाबियाँ सौंप दीं। वर्तमान मुकदमे का निर्णय लंबित होने तक यह परिसर 1998 से खाली पड़ा हुआ है। प्रतिवादी सं. 2, श्री वीरेन्द्र कुमार गोयल अप्रैल, 2008 में परिसर के नियमित दौरे पर गए थे, और परिसर में बड़े पैमाने पर किए जा रहे नवीनीकरण को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। पूछताछ करने पर, उन्हें सूचित किया गया कि वादीगण द्वारा किसी बी.पी.ओ./कॉल सेंटर को रखा गया है। इस प्रकार

प्रतिवादी ने अं.आ. सं. 4800/2008 के माध्यम से एक आवेदन दायर किया जिसमें वादी को परिसर में व्यवसाय/नवीनीकरण करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने और वादीगण को परिसर की चाबियाँ माननीय न्यायालय को सौंपने का निर्देश देने की माँग की गई। वादीगण के अधिवक्ता ने 25.04.2008 को न्यायालय में एक बयान दिया कि किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष का हित नहीं बनाया जाएगा और एक वचन दिया, जो अभी भी जारी है।

6. इसके बाद, वादीगण की ओर से एक उत्तर दायर किया गया जिसमें आश्चर्यजनक रूप से यह दावा किया गया है कि वादी ने पिछले कुछ वर्षों से अपना कार्यालय और व्यवसाय शुरू किया है और उक्त परिसर में व्यापक नवीनीकरण कर रहा है।

7. प्रतिवादी ने अं.आ. सं. 4800/2008 के वादी के उत्तर का संदर्भ दिया है जिसमें प्राख्यान दिया गया है कि वह सह-मालिक है और वाद की संपत्ति के बेसमेंट पर उसका कब्ज़ा है और वह रखरखाव के साथ-साथ उक्त संपत्ति की मरम्मत पर भी खर्च कर रहा है। प्रतिवादीगण ने न तो खर्च किया है और न ही रखरखाव के लिए धन की पेशकश की है। वादी कुछ वर्षों से परिसर से अपना कार्यालय और व्यवसाय चला रहा है और इसमें भारी निवेश कर रहा है और करों का भुगतान कर रहा है। यदि वादी सं. 1 द्वारा संपत्ति के रखरखाव

के लिए प्रयास नहीं किया गया होता, तो यह संपत्ति खंडहर और बेकार हो गई होती।

8. प्रतिवादी सं. 2 ने कहा है कि निजी कार्यालय और व्यवसाय चलाने के लिए वाद की संपत्ति के बेसमेंट को हड़पने का वादी का कार्य स्पष्ट रूप से अवैध है। परिसर की चाबियाँ बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वादी और प्रतिवादी सं. 2 को सौंप दी गई थीं। परिसर को खाली रखा गया क्योंकि वादी और प्रतिवादी सं. 2 और 3 सह-मालिक थे। वादी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बेसमेंट के कब्जे को एकतरफा रूप से हड़प नहीं सकता है।

9. प्रतिवादी सं. 2 ने प्राख्यान दिया है कि उसकी जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में किराया लगभग 65 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा और उस स्थान का किराया, जो अन्य सह-मालिकों को छोड़कर वादी द्वारा अवैध रूप से और अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, 3 लाख रुपये प्रति माह या अधिक है।

10. यह दावा किया गया है कि वादी वाद के निपटान में देरी कर रहा है, जिससे प्रतिवादीगण वाणिज्यिक संपत्ति के मूल्यवान भाग से वंचित हो रहे हैं। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि वादी को प्रति माह 1,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 अपने हिस्से के संबंध में संपत्ति के बाजार किराए का सही हकदार है। इसके अतिरिक्त, वादी को प्रतिवादी सं. 2 को 54,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देने की

प्रार्थना की गई है, जो पिछले तीन वर्षों के लिए संपत्ति के किराये का उसका हिस्सा है।

11. वादी ने अपने उत्तर में प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि वर्तमान आवेदन वादी, एक विधवा और उसके बच्चों को पारिवारिक संपत्तियों, व्यवसाय और उससे होने वाली आय पर उनके अधिकार से वंचित करने के एकमात्र उद्देश्य से दायर किया गया है। यह एक जवाबी हमला है जो बहुत देर से हुआ है और सुंदर नगर की संपत्ति पर वादी के दावे पर बाद में विचार किया गया है। वादी वाद की संपत्ति के दोषपूर्ण कब्जे में नहीं हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण स्वर्गीय श्री सुरेश गोयल (प्रतिवादी सं. 1 के बेटे) की पत्नी और दो बच्चे हैं, जिन्हें 1972 में श्री सुरेश गोयल के निधन के बाद उनके संयुक्त परिवार के घर और व्यवसाय से बाहर निकाल दिया गया था। वादी सं. 1 और 2 वादी सं. 3 के नाबालिग बच्चे हैं जिनके विरुद्ध आवासीय घर से बाहर निकालने और पारिवारिक व्यवसाय और अन्य संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों में किसी भी अधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से झूठे आपराधिक मामले दायर किए गए थे।

12. वादी ने बयान दिया है कि प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने सभी संभव तरीकों से वादी को संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय, संपत्ति और घर में हिस्सेदारी के अधिकार से वंचित कर दिया है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह प्राख्यान दिया जाता है कि प्रतिवादीगण पिछले 37 वर्षों से वादी को छोड़कर वाद की 95%

संपत्तियों का उपभोग कर रहे हैं। पक्षकारगण की विभिन्न संपत्तियों का पूंजीगत मूल्य लगभग 40-50 करोड़ रुपये होगा, इसके अलावा इन संपत्तियों से आय प्रति वर्ष कुछ करोड़ (लगभग 21 लाख प्रति माह) है। यह प्राख्यान दिया गया है कि वादी सं. 1 के पास संपूर्ण वाणिज्यिक और आवासीय संपत्ति में से केवल 29ए/1 आसफ अली रोड का भौतिक कब्ज़ा है; वादी को छोड़कर सभी प्रतिवादी सं. 2 और 3 के कब्ज़े में हैं, और वादी संख्या 2 और 3 के पास एक भी आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति नहीं है।

13. प्रतिवादी सं. 2 और 3 पिछले 37 वर्षों से दोषपूर्ण ढंग से व्यवसाय से किराये / साख रिटर्न के रूप में करोड़ों रुपये का आनंद ले रहे हैं, जो पिछले 37 वर्षों से प्रति वर्ष 10-15 करोड़ रुपये है, जबकि वादी पर बोझ डाला गया है और उसने सभी व्यावसायिक देनदारियों का एक तिहाई भुगतान भी कर दिया है।

14. यह प्राख्यान दिया गया है कि सभी वाणिज्यिक संपत्तियाँ, जो वाद संपत्तियाँ हैं, दिनांक 01.05.1964 के एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें वादी सं. 1 और 2 के पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार गोयल एक लाभार्थी थे और और दो अन्य संपत्तियाँ उसके जीवनकाल के दौरान संयुक्त पारिवारिक व्यवसाय निधि से बनाई गई थीं। स्वर्गीय आनंद प्रकाश गोयल या प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा कोई भी संपत्ति नहीं बनाई गई है। इसके बावजूद, प्रतिवादी सं. 2 और 3 का उन संपत्तियों में से 12 पर कब्ज़ा है, जिनका

पूंजीगत मूल्य लगभग 60-70 करोड़ रुपये है, जबकि संपत्तियों का किराया मूल्य और आय लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है। वादी को छोड़कर संपत्तियों पर उनका विशेष कब्ज़ा है, भले ही वादीगण ने स्वीकार किया है कि उनकी उनमें हिस्सेदारी है। यह प्राख्यान दिया गया है कि समानता और न्याय के हित में, आवेदन में वर्णित सभी वाणिज्यिक संपत्तियों पर समग्रता से विचार किया जाना चाहिए और निपटारा किया जाना चाहिए।

15. आगे यह भी प्राख्यान दिया गया है कि प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार के अंतःकालीन लाभ के हकदार नहीं हैं। वे स्वर्गीय आनंद प्रकाश गोयल की विभिन्न विलों में से एक के माध्यम से आसफ अली रोड की संपत्ति में 50% अधिकार का दावा कर रहे हैं, जो विवादित है। इसके अतिरिक्त, स्वर्गीय आनंद प्रकाश गोयल (प्रतिवादी सं. 1) की संपत्तियों में हिस्सेदारी लेखे देने के अधीन है और जब तक लेखे का विवरण नहीं दिया जाता, तब तक स्वर्गीय आनंद प्रकाश गोयल की संपत्तियों का निपटान किसी भी विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता है और संपत्तियों और इन संपत्तियों से होने वाली आय वादी के दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी हैं।

16. यह बयान दिया गया है कि 1999 से, वाद संपत्ति न्यायालय के आदेश के अधीन है और किसी भी किराये की आय अर्जित करने में असमर्थ हो गई है। एक ओर, प्रतिवादी दावा कर रहा है कि वादी को संपत्ति को किराये पर देने से रोका जाए और दूसरी ओर, वह इस संपत्ति से किराये का दावा कर रहा है

जिसे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्राप्त आदेशों के कारण किराये पर नहीं दिया जा सकता है।

17. यह स्पष्ट किया गया है कि बेसमेंट जो विषयगत संपत्ति है, जर्जर स्थिति में था और उस समय, कोई भी प्रतिवादी इसके रखरखाव के लिए आगे नहीं आया। 2005 में, बेसमेंट में पानी जमा होने के कारण पूरी इमारत को खतरा था और तब वादी सं. 1 ने संपत्ति की रक्षा के लिए इसे उपयोग के योग्य बनाने हेतु लाखों रुपये खर्च किए। अब, अचानक प्रतिवादीगण अपने कथित हिस्से का दावा करते हुए सामने आ गए हैं।

18. वादीगण ने 2001 की शुरुआत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर बेसमेंट को किराये पर देने की अनुमति माँगी थी क्योंकि उनके लिए संपत्ति का रखरखाव करना मुश्किल हो रहा था। प्रतिवादीगण ने न तो रखरखाव के लिए भुगतान करने की पेशकश की और न ही संपत्ति को किराये पर देने के वादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। दावा किया गया है कि यह आवेदन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

19. **गुणागुण के आधार पर**, आवेदन में दिए गए प्रकथनों को अस्वीकार किया जाता है और यह कहा गया है कि आवेदन में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।

20. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

21. वादीगण ने विभाजन, यह घोषणा करने के लिए कि वादी किरायेदारी के लाभ का आनंद लेने के हकदार हैं जो न तो बिक्री योग्य हैं और न ही विभाज्य हैं; लेखे का विवरण देने और ब्याज सहित 4,85,025.90 रुपये की वसूली और वादपत्र में उल्लिखित शेरों/संपत्तियों की वसूली के लिए एक वाद दायर किया है। वादीगण ने यह भी माँग की थी कि वादी सं. 2 के विवाह के भरण-पोषण के लिए प्रावधान किया जाए, जो प्रतिवादी सं. 1, आनंद प्रकाश गोयल के मृत बेटे स्वर्गीय सुरेश कुमार गोयल की बेटी, और प्रतिवादी सं. 1, आनंद प्रकाश गोयल के पुत्र प्रतिवादी सं. 2 और 3 श्री वीरेंद्र कुमार गोयल और श्री रविंदर कुमार गोयल की भतीजी है।

22. वादीगण का मामला है कि एचयूएफ़ मैसर्स आनंद प्रकाश एंड संस के स्वामित्व में कई संपत्तियाँ थीं, जिनका विवरण अनुसूची क में दिया गया था। ऐसी कई संपत्तियाँ थीं जिनका स्वामित्व विशेष रूप से स्वर्गीय सुरेश कुमार गोयल (जिनकी मृत्यु 11.08.1972 को हुई) के पास थी, जिनका विवरण अनुसूची ख में दिया गया है। वादीगण, जो स्वर्गीय सुरेश कुमार गोयल के बेटे, बेटी और पत्नी हैं, ने परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वामित्व वाली विभिन्न संपत्तियों का विवरण दिया था और अपने हिस्से के अनुसार विभाजन, लेखे का विवरण देने और इसकी वसूली का दावा किया था।

23. वाद के लंबित रहने के दौरान, चार आवेदन दायर किए गए थे, नामित अं.आ. सं. 2039/2009, जिसमें 15,000/- रुपये की अंतरिम राशि को बढ़ाने

की माँग की गई थी, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था; अं.आ. सं. 9180/2009 जिसमें प्रतिवादीगण के कब्जे वाली दुकानों के संबंध में मुआवज़े की माँग की गई थी; अं.आ. सं. 2657/2009 और अं.आ. सं. 8468/2009 जिसमें प्रतिवादी सं. 2 और 3 ने बेसमेंट में हिस्सेदारी का दावा करते हुए, आसफ अली रोड पर कुछ संपत्तियों के उपयोग और कब्जे के संबंध में वादीगण को निर्देश जारी करने की माँग की थी।

24. प्रतिवादी सं. 2 और 3 को आदेश दिनांक 29.03.1985 द्वारा सुंदर नगर वाले घर में रहने के वादीगण के अधिकार के बदले 01.03.1985 से प्रति माह 3,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 07.03.1988 के आदेश के माध्यम से यह राशि बढ़ाकर 3500/- रुपये प्रति माह कर दी गई और उसके बाद दिनांक 27.10.1997 के आदेश के माध्यम से इसे बढ़ाकर 15,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया। पिछले आदेश में, यह देखा गया कि स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार गोयल सुंदर नगर संपत्ति में 24.25% हिस्सेदारी के साथ सह-मालिक थे। चूँकि वादीगण को बेदखल कर दिया गया था और उक्त संपत्ति पर उनका कब्ज़ा नहीं था, इसलिए वे संपत्ति का उपभोग करने के अपने अधिकार से वंचित थे और इस प्रकार उन्हें मुआवज़े का हकदार माना गया और संपत्ति में उनके अधिकार को मान्यता देते हुए राशि को बढ़ाकर 15,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध आ.प्र.अ. (मू.प.) 268/1997 और सि.वि. 386/1998 को प्रस्तुत किया गया था जिसे

खारिज कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में वि.अनु.या. (सि) सं. 8389/1998 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें राशि को घटाकर 10,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया।

25. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2010 के आदेश के तहत इस राशि को बढ़ाकर 80,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया। उसी आदेश से, वर्तमान आवेदन अं.आ. 8468/2009 जो विचाराधीन है, खारिज कर दिया गया था जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई थी, और इसे नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया गया था।

26. प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा दिए गए प्राख्यान यह हैं कि वादीगण आसफ अली रोड की संपत्ति के बेसमेंट के कब्जे में हैं, जिसे वे अपने कार्यालय के लिए उपयोग कर रहे हैं जिसमें प्रतिवादीगण का भी हिस्सा है। प्रतिवादीगण ने दावा किया है कि वे वादीगण द्वारा बेसमेंट के उपयोग और कब्जे के लिए संबंधित अंतःकालीन लाभ के हकदार हैं। यह देखा जा सकता है कि यह विभिन्न संपत्तियों/व्यवसायों, जिनके संयुक्त स्वामित्व का दावा किया गया है, के संबंध में विभाजन और लेखे देने के लिए एक वाद है। वादीगण ने यह भी दावा किया है कि अनुसूची ख में विभिन्न संपत्तियाँ सूचीबद्ध हैं, जिनके विभाजन का भी दावा किया गया है, जिनके विशेष मालिक श्री सुरेश कुमार गोयल थे।

27. इस प्रकार इस मामले में कई संपत्तियाँ शामिल हैं जिनके संबंध में विभाजन की माँग की गई है। कुछ संपत्तियाँ, हालाँकि संयुक्त रूप से स्वामित्व में हैं, कुछ पक्षकारगण द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जा रही हैं। लेखे का विवरण भी माँगा गया है। एक पक्ष ने रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था जिसे खारिज कर दिया गया। यह मामला 1982 से आज तक लंबित है, न तो कोई रिसीवर नियुक्त किया गया है और न ही विभिन्न संपत्तियों/व्यवसायों के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा प्राप्त लाभों/फ़ायदों का कोई लेखा दिया गया है, जो इस वाद का विषय है। इस स्तर पर एक संपत्ति के लेखों का विवरण देने की प्रकृति में कोई भी परीक्षण करने का इस न्यायालय के लिए कोई प्रत्यक्ष औचित्य नहीं है, जबकि अन्य संपत्तियों के संबंध में ऐसा नहीं किया गया है।

28. मामला 1982 से इतना आगे बढ़ चुका है और पूरा होने के निकट है और प्रतिवादीगण के साक्ष्य के लिए सूचीबद्ध है। संपत्तियों के संबंधित शेयरों और अंतःकालीन लाभों के अंतरिम अधिकार के बारे में इस स्तर पर कोई भी जाँच करने से, जबकि यह आज तक नहीं किया गया है, केवल अनावश्यक देरी होगी और यह विचारण को और पटरी से उतार देगा, जो इस मामले की उम्र को देखते हुए, न्याय के हित में नहीं होगा। इस कार्य को करने से केवल वाद में देरी होगी क्योंकि प्रश्नगत प्रत्येक संपत्ति पर अलग से विचार करना होगा। यह भी देखा जा सकता है कि जहाँ वादीगण अपनी आजीविका कमाने के लिए एक

संपत्ति का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, वहीं कई अन्य संपत्तियाँ भी हैं जो प्रतिवादीगण के पास हैं, जिनसे वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कोई लेखा नहीं है। साथ ही, वादीगण संपत्ति का उपयोग अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, और यह नहीं कहा जा सकता है कि आसफ अली की संपत्ति में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं।

29. जहाँ तक सुंदर नगर की संपत्ति का प्रश्न है, जो टिप्पणी की गई है वह यह है कि वादीगण, जो मृतक सुरेश कुमार गोयल की पत्नी और उसके दो बच्चे हैं, को उक्त संपत्ति में उनके निवास के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और चूँकि उन्होंने कहीं और निवास ले लिया है, यह राशि केवल उन्हें अपने निवास के खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दी गई है और यह लेखे देने या उक्त संपत्ति में उनके हिस्से की मान्यता के माध्यम से नहीं है।

30. इस चरण में प्रतिवादी सं. 2 और 3 द्वारा माँगी गई आसफ अली की संपत्ति में उनके हिस्से की सीमा तक अंतःकालीन लाभ को अन्य वाद संपत्तियों के साथ संबंधित चरण में विचार करने के लिए स्थगित कर दिया गया है।

31. आवेदन का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)  
न्यायाधीश

10 जनवरी, 2023

पीए

*(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)*

**अस्वीकरण :** देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।